

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी वाड़मेर

पीठारीन अधिकारी प्रतिष्ठा पिलानिया आर ए एस
राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 32 / 2022 / वाड़मेर

अपीलांत

रेस्पोंडेंटगण

- | | | |
|--|------|---|
| 1. गोहम्मद अली पुत्र तालव | वनाम | 1. वशीर अहमद पुत्र सलीम |
| 2. मोगन पुत्र तालव जाति
मुसलमान निवासी रोड़वा
जिला वाड़मेर | | 2. तालव पुत्र सलीम
3. उगत पत्नी सलीम जाति मुसलमान
निवासी रोड़वा तहसील रोड़वा जिला
वाड़मेर
4. ईशाक पुत्र सरीफ खां जाति मुसलमान
निवासी रासवानी तहसील रामसर
5. श्रीमान तहसीलदार सेड़वा |

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध राहायक कलक्टर रोड़वा द्वारा राजस्व वाद संख्या 53/2021 बअनवान गोहम्मद अली वनाम वशीर अहमद वगै. में पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 11.03.2022 के विरुद्ध पेश हुई।

उपरिस्थिति

1. वकील श्री मुकेश जैन अपीलान्त की ओर से।
2. वकील श्री केसराराम विश्णोई रेस्पोंडेंट संख्या 01 से 03 की ओर से।

निर्णय

दिनांक:- 28.07.2022

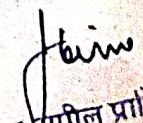
अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अंतर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश हुआ। मौजा सेड़वा तहसील रोड़वा के खेत खसरा संख्या 170 रकबा 17.08 बीघा भूमि अवस्थित है। उक्त वादग्रस्त भूमि में अपीलांत/वादीगण व रेस्पोंडेंट संख्या 01 से 04 की संयुक्त खातेदारी की भूमि है तथा पक्षकारान अपने अपने हिस्से के अनुसार कब्जा काश्त करते आ रहे हैं तथा इसी हिस्से माफिक अपीलांत व रेस्पोंडेंटस का अपीलाधीन आराजी पर काबिज है। वादीगण अपने हिस्से की भूमि पर रहवासी ढाणी, चारागाह, पशु वाड़े एवं टांके टयूववेल बने हुए। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांतगण को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित की गई प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के खिलाफ है, जिसके विरुद्ध हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांत ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष हस्तगत वाद पेश होने पर प्रतिवादीगण/रेस्पोंडेंट को नोटिस जारी हुए लेकिन वावजूद तलबी के रेस्पोंडेंटस की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं होने पर प्रतिवादीगण के विरुद्ध दिनांक 01.12.2021 को एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई

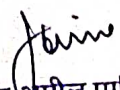
राजस्व अपील प्राधिकारी
वाड़मेर

गई तथा वादीगण की ओर से साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने के पश्चात दिनांक 01.12.2021 को प्रारम्भिक डिफ्री जारी की गई, तत्पश्चात दिनांक 29.12.2021 को प्रतिवादी संख्या 01 से 03 की ओर से प्रार्थना-पत्र के अन्तर्गत आदेश 09 नियम 13 प्रस्तुत किया गया तथा पत्रावली जबाब हेतु दिनांक 18.01.2022 को मुर्कर की गई। रेस्पोंडेंटस की ओर से दिनांक 24.03.2022 को एक प्रार्थना-पत्र त्वरित सुनवाई का व पत्रावली पेशी पर लेने का प्रस्तुत किये जाने पर पत्रावली दिनांक 24.03.2022 की जगह 11.03.2022 को मुर्कर की गई। रेस्पोंडेंटस द्वारा पेश प्रार्थना-पत्र आदेश 09 नियम 13 को विद्धो किये जाने का प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने उसी दिन दिनांक 11.03.2022 को रेस्पोंडेंटस के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र को खारिज कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रारम्भिक डिफ्री की पालना में तहसीलदार सेड़वा को विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु अधिकृत किया गया था परन्तु तहसीलदार सेड़वा द्वारा वादग्रस्त खेत पर जाये बिना पटवारी हल्का व आर आई के मार्फत उक्त विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु निर्देशित किया जिस पर पटवारी हल्का द्वारा उतरदाता/प्रतिवादीगण के प्रभाव में आकर कब्जा काश्त के विपरीत विभाजन प्रस्ताव तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय पेश किया गया। अपीलांट को बिना पूर्व सूचना के आर.आई द्वारा विभाजन प्रस्ताव मौके की स्थिति के विपरित तैयार किया गया, जिस पर अपीलांट के हस्ताक्षर नहीं है तथा एकपक्षीय रूप से तैयार विभाजन प्रस्ताव को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिस पर अपीलांट व उसके अधिवक्ता द्वारा विभाजन प्रस्ताव पर एतराज किया गया। अपीलांटगण द्वारा विभाजन प्रस्ताव पर एतराज करने के बावजूद भी अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया। राजस्थान टिनेन्सी (राजस्व मण्डल) 1955 के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है तथा तहसीलदार सेड़वा द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में पेश विभाजन प्रस्ताव मौके के प्रतिकूल बनाकर अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया। यह बंटवारा By Metes & Bounds सिद्धांत के आधार पर नहीं किया गया है। अपीलांटगण को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अपीलांट को सुने बिना निर्णय पारित किया गया है। अपीलांट संख्या 01 ने हाजा न्यायालय के समक्ष अपील को विद्धो करने के संबंध में एक आवेदन दिनांक 15.06.2022 को पेश किया जिस पर मेरा एतराज है, उसके उपरांत न्यायालय उस आवेदन को स्वीकार करता है तो न्यायालय का विवके है लेकिन मेरी अपील तो भी फिर भी चलेगी। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे। अपीलांटगण के अधिवक्ता ने अपने कथन के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत पेश किये:-


राजस्व अपील प्राधिकारी
बाडमेर

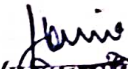
वकील रैपोर्ट संख्या 01 से 03 ने बहरा करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्त को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई जो न्यायोचित है। हिस्सों को लेकर अपीलान्त द्वारा किसी भी प्रकार का उजर पेश नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिस विभाजन प्रस्ताव के आधार पर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है विधि सम्मत है जिसमें किसी तरह की कमी नहीं है क्योंकि तहसीलदार रोड़वा द्वारा मौके पर पक्षकारान के कब्जा काश्त के अनुसार उभयपक्षकारान के रूबरू विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया है जो विभाजन प्रस्ताव मौके पर पक्षकारान के कब्जा काश्त अनुसार सही है। अपीलान्त संख्या 01 स्वयं ने न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर जाहिर किया कि कबह अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय से संतुष्ट है तथा उक्त निर्णय के विरुद्ध किसी भी प्रकार की अपील चलाना नहीं चाहता तथा अपील को विद्धो करने का निवेदन किया। अपीलान्त द्वारा उतरदाता को नाहक तंग व परेशान करने की नियत से गलत रूप से अपील पेश की गई है जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने वादग्रस्त भूमि की सही विधिवत हिस्से अनुसार घोषणा कर बंटवाड़ा किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुरूप पारित किया गया है जिसमें किसी तरह की कमी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय By Metes & Bounds सिद्धांत के आधार पर पारित किया गया है और सहखातेदारों के मध्य विभाजन बराबर-बराबर किया गया है। किसी का हिस्सा कम-ज्यादा नहीं किया गया इसलिए अपीलान्त की अपील खारिज फरमायी जावे।

पत्रावली का अवलोकन व विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अपीलान्त संख्या 01 स्वयं ने दिनांक 15.06.2022 को न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र वास्ते अपीलान्त संख्या 01 के हिस्से तक अपील विद्धो करने बाबत पेश कर अंकित तथ्यों को दौहराते हुए बताया कि "अपीलान्त संख्या 01 द्वारा उपरोक्त अनवान की कोई अपील श्रीमानजी के सक्षम पेश नहीं की गई थी तथा अपीलान्त संख्या 01 आज से पूर्व कभी भी श्रीमान न्यायालय में हाजिर भी नहीं हुआ है तथा अपीलान्त संख्या 02 जो अपीलान्त संख्या 01 का सगा भाई है, ने सदभाविक रूप से मुझे अपीलान्त संख्या 01 से खाली पेपरों पर हस्ताक्षर करवा लिये तथा उन पर अपीलान्त संख्या 02 ने अपने साथ मेरी तरफ से भी अपील पेश कर दी जबकि यह अपील अपीलान्त संख्या 01 द्वारा कभी भी पेश नहीं की गई है। उतरदाता द्वारा जब मुझे इस संबंध में बताया तब मुझे अपील के संबंध में जानकारी हुई, मैं अपीलान्त संख्या 01 अधीनस्थ

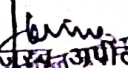

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाडमेर

न्यायालय के निर्णय से सतुष्ट हैं तथा उक्त निर्णय के विरुद्ध किसी भी प्रकार की अपील चलाना नहीं चाहता हूँ। तथा अपील को इसी स्तर पर दिव्रो करने का निवेदन किया गया। लिहाजा अपीलांट संख्या 01 के हिस्से तक अपील को दिव्रो करने के आदेश दिये जाते हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट संख्या 02 को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिब्री उभयपक्ष की उपस्थिति में बहस सुनने के पश्चात पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय प्राप्त विभाजन प्रस्ताव बाकायदा तहसीलदार सेडवा ने नियमानुसार भूमि की गुणवत्ता, स्थायी अलामात/कब्जे/मार्ग को मद्देनजर रखते हुए बनाया जाकर पेश किया, जिस पर दिनांक 11.03.2022 को अंतिम डिब्री जारी की गई। उपरोक्त विभाजन प्रस्ताव तैयार करते वक्त अपीलांट मीके पर उपस्थित रहे लेकिन हस्ताक्षर करने से इंकार किया। हस्तगत विभाजन प्रस्ताव तैयार करते वक्त राजस्थान टिनेन्सी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 20 से 21 की पूर्ण रूप से पालना की गई है। अपीलांट संख्या 02 येन-केन प्रकारेण मामले में अवरोध डालकर इसे अनावश्यक चुनौती देने की मंशा रखते हैं और वे न्यायालय में सदभावना के साथ स्वच्छ हाथों से नहीं आए हैं। अपीलाधीन निर्णय विधिसम्मत एवं नियमानुसार By metes & Bound सिद्धांत के अनुसार तैयार किये गए तहसीलदार सेडवा से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर पारित किया गया है जिसमें किसी भी प्रकार की विधिक त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिब्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित की गई जिसमें किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं हो रही है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर सेडवा द्वारा राजस्व वाद संख्या 53/2021 बअनवान मोहम्मद अली बनाम वशीर अहमद वगै. में पारित निर्णय एवं अंतिम डिब्री दिनांक 11.03.2022 को यथावत रखा जाता है।


 राजस्थान (सिद्धांत प्राधिकारिया)
 राजस्व अपील प्राधिकारी
 बाड़मेर

यह निर्णय आज दिनांक 28.07.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


 राजस्थान अपील प्राधिकारी
 बाड़मेर